भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1979

(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण एमएसएमई क्लस्टर

1979. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से वैश्विक महामारी के बाद की रिवर्स माइग्रेशन की प्रवृत्ति के मद्देनजर, कृषि उद्योगों को प्रोत्साहित करके , ग्रामीण स्टार्टअप को बढ़ावा देकर और कौशल आधारित स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार केंद्रों में बदलने की संभावना तलाशी है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे के लिए संघर्ष जारी है और यदि हां , तो बैंकिंग सुविधा से वंचित गांवों में डिजिटल बैंकिंग , माइक्रो-फाइनेंसिंग और फिनटेक समाधानों का विस्तार करके पूर्ण वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए क्या पहल की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक के कई भागों , विशेषकर दावणगेरे जिले में बार-बार पड़ने वाले सूखे की समस्या से निपटने के लिए भूमिगत जलभंडार पुन: भरण , सामुदायिक वर्षा जल संचयन और ड्रिप सिंचाई के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे नवोन्मेषी जल संरक्षण मॉडलों पर विचार किया है; और

(घ) क्या स्थानीय उद्यमियों , बुनाई सहकारी समितियों और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता के लिए कृषि और वस्त्र उद्योग में मजबूत आधार वाले दावणगेरे में ग्रामीण एमएसएमई क्लस्टर स्थापित करने की कोई योजना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और पलायन को रोकने के उद्देश्य से , ग्रामीण विकास मंत्रालय आजीविका के अवसरों को बढ़ाने , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने , बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर मुख्य ध्यान देने के साथ कई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) , प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) शामिल हैं। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम (एमकेएसपी) और स्टार्ट-अप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के माध्यम से कृषि और गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। आरएसईटीआई बैंक द्वारा संचालित , ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एक प्रशिक्षण संस्थान है जो कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।

इसके अलावा , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है , जो शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरा करने , कृषि विकास में सहायता देने और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए लाभकारी स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र घटक "कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्रों की स्थापना" का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा , कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करके , कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर पैदा करके ग्रामीण क्षेत्रों को बदलने में सहायक रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक फसल के बाद वाले बुनियादी ढाँचा को विकसित करके , नुकसान को कम करके और बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करके किसानों की आय बढ़ाना है। यह गोदामों, कोल्ड स्टोरेज , छंटाई इकाइयों और राईपनिंग चैम्बरों के माध्यम से फार्म गेट भंडारण, लोजिस्टिक्स और मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है , जिससे किसानों को पहले से कम मध्यवर्तियों के साथ बड़े बाजारों तक पहुँचने में मदद मिलती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को ऋण प्रदान करती है। इन उपायों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना , पलायन को कम करना और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ाना है।

(ख): यह सरकार डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत है। इसके समाधान के लिए, पूर्ण वित्तीय समावेशन प्राप्त करने हेतु विभिन्न पहल की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) बैंकिंग सुविधा से वंचित हर परिवार को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सहायक रही है। सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंकों ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने और उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे (i) ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल वित्त - ग्रामीण नागरिकों के लिए उपलब्ध डिजिटल वित्त विकल्पों पर जागरूकता सत्र आयोजित करने के लिए जागरूकता और पहुंच बनाना (डीएफआईएए) योजना; (ii) प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के सक्रिय सहयोग से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया है ; (iii) आरबीआई डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ; (iv) आरबीआई डिजिटल बैंकिंग का उपयोग करते समय सतर्कता बरतने के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से सार्वजनिक जागरूकता मीडिया अभियान चला रहा है। आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग की सुविधा , डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा आदि जैसे विषयों पर बहुभाषी मीडिया अभियान भी चलाए हैं ; (v) आरबीआई वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित करता है ; (vi) बैंक अपने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के जरिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और * 99# (यूएसएसडी) के जरिए "डिजिटल होने पर" विशेष शिविर आयोजित करते हैं ; (vii) बैंकों की ग्रामीण शाखाएं वित्तीय जागरूकता संदेश पुस्तिका के सभी संदेशों और दो डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूपीआई और * 99# यूएसएसडी को शामिल करते हुए शिविर आयोजित करती हैं; और (viii) बैंकिंग संवाददाता स्थानीय आबादी के साथ सुपरिचय होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लेनदेन को सुविधाजनक बनाते हुए जागरूकता भी पैदा करते हैं।

इसके अलावा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) डाकघरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करता है , जिससे वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का डीएवाई-एनआरएलएम डिजिटल वित्त को बढ़ावा देने और बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटरों के सहयोग से बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी (बीसी सखी) के रूप में

एसएचजी महिलाओं की तैनाती के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच प्रदान कर रहा है, जहाँ लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं है।

(ग): सरकार कर्नाटक राज्य सहित जल की कमी के मुद्दे के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार , केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश में लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएँ तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय डब्ल्यूडीसी - पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन कर रहा है जो मुख्य रूप से वर्षा सिंचित/क्षरित भूमि के विकास पर केंद्रित है। इस योजना में की जाने वाली कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ रिज एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी उगाना, चारा विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत किए गए उपाय खेती के तहत क्षेत्र बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करती हैं। इसी तरह , कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) की एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है , जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।

(घ): सरकार, एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों के पंजीकरण के लिए योजना (एसएफयूआरटीआई) का कार्यान्वयन कर रही है , ताकि पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और इसके लिए कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित किया जा रहा है, ताकि उनकी दीर्घकालिक स्थिरता और बड़े पैमाने की लागत को सहायता प्रदान की जा सके। यह योजना पारंपरिक उद्योगों के कारीगरों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण , प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, नवाचार, डिजाइन कार्यकलाप, विपणन क्षमता, बेहतर पैकेजिंग और विपणन बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। पारंपरिक उद्योगों को मोटे तौर पर खादी उद्योग, ग्रामोद्योग और कॉयर उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार , कर्नाटक के दावणगेरे जिले में कपड़ा उद्योग में हरिहर खादी क्लस्टर नामक एक क्लस्टर कार्य कर रहा है।

*****